

संपादकीय

उसके पास सवारी के
लिए कोई टिकट नहीं

पिछले दशक में राज्य और लोकसभा चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस बदलाव को नारी शक्ति या महिला शक्ति की अभिव्यक्ति घोषित करके, राजनीतिक दलों ने नियमों का पालन करने और लक्षित योजनाओं को लागू करने के अलावा वास्तव में कुछ किए बिना महिलाओं को सशक्त बनाने का श्रेय आसानी से ले लिया है। लोकसभा चुनावों के लिए अभियान शुरू होने के साथ ही महिलाएं, एक अविभाजित जनसमूह के रूप में, फोकस में हैं। उनका मूल्य और भूमिका उन तरीकों से मापने योग्य है जो प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाते हैं जिसमें भाजपा ने खुद को अपनी पिछली सीटों के खिलाफ खड़ा किया है – एनडीए के लिए शब्दकी बार 400 पारश जैसे नारे के साथ – और कांग्रेस के असंगठित विपक्ष के खिलाफ, क्षेत्रीय दल और अन्य छोटे खिलाड़ी। इंडिया ब्लॉक में इन पार्टियों का प्रवेश और निकास उनकी भूमिका को अस्पष्ट बनाता है – कभी–कभी चुनौती देने वाला, कभी–कभी रक्षक – क्योंकि उनकी भूमिकाएँ राज्यों में भिन्न–भिन्न होती हैं। चुनावी मौसम में, नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, महिलाएं अब स्टॉक भाषण का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। महिला मतदाताओं को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा 2019 से तेज हो गई है। इसका कारण स्पष्ट रूप से महिलाओं की बढ़ती दृश्यता और लक्षित लाभ की गारंटी

लोकसभा चुनाव - यादें सुकुमार सेन और टीएन शेषन की

लोकसभा चुनाव - यदें सुकुमार सेन और टीएन शेषन की

आर. के.
पाठ्य बाबू

एक बार फिर से दशा लोकसभा नवां के लिए तैयार है। लोकसभा नवां की घोषणा अब कभी भी हो जानी है। देश में चारों तरफ लोकसभा चुनाव का माहौल बनता चला जा रहा है। वास्तव में यह तीतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण खासमखास उत्सव भी है। इस उत्सव में इसबार 86 करोड़ मतदाता ने मताधिकार का प्रयोग कर दिये। इनमें 47 करोड़ महिला वोटर थीं। इस उत्सव में देश के 28 राज्य और नौ केंद्र शासित शामिल हुए। लोकसभा चुनावों को सफलता करने करवाने की जिम्मेदारी डेढ़ करोड़ सरकारी अफसरों पर होगी। सब सवा करोड़ मतदान केंद्रों में से कर मतदाता देश के 543 लोकसभा सांसदों का चुनाव करेंगे। सब आंकड़े गवाह हैं कि भारत बड़ा और व्यापक संसदीय चुनाव भर में कहीं और नहीं होता। अर्थात्, भारत में अब तक लोकसभा

हमास—हौथी—हिजबुल्लाह लड़ाई की योजना बना रहा है। वाशिंगटन पाकिस्तान में मंदी से विचलित नहीं हो सकता। जबकि वह इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि उसकी हथियार साझेदार सेना ने चुनाव नतीजों में हस्तक्षेप करके गलती की है, जैसा कि उसने पिछली बार किया था, जब उसने वैध रूप से चुने गए नवाज को बाहर कर दिया था और एक कुख्यात क्रिकेटर से नेता बने को लाया था, यह खान की सहानुभूति थी तहरीक—ए—तालिबान असली लाल झंडा था। इमरान ने खुले तौर पर तहरीक—ए—तालिबान पाकिस्तान और अन्य चरमपंथी समूहों से उत्तर वजीरिस्तान में बसने का आग्रह किया था, जिन्होंने अफगानिस्तान में शरण ली थी और पाकिस्तान सेना और नागरिकों को शिक्षण बनाया था। खैबर पख्तूनख्वा प्रशासन में इमरान की पीटीआई की वापसी को देखते हुए, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर शहबाज के शपथ लेने के कुछ घंटों के भीतर कोर कमांडरों व बैठक बुलाई।

के दशक तक, बूथ क्षेत्रगत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल काफी प्रचलित हो गई थी, हालाँगी भारतीय कम्प्युनिस्ट पार्टी (भार्क्सवाच) ने श्वेत प्रबधनश नामक एक ची का अभ्यास किया था, जिसमें इन कैडर के कार्यकर्ता एक लाइन खड़े होकर मतदान करते थे। यह मानना होगा कि पहले चुनाव आयुक्तों के रूप में जिस परंपरा को सुकुमार सेन ने शुरू किया था उसे अलेकर जाने वाले कुशल चुनाव आयुक्तों में टी.एन.शेषन ने सब अग्रणी भूमिका निभाई थी। आगे भी बुद्धिजीवी समाज वाले तो यह कहते हैं कि अगर टी.एन.शेषन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते, तो देश में चुनावों के नियम पर धोखाधड़ी और धंधंली का आलाजारी ही रहता। उन्होंने 1990 दशक में चुनाव आयोग के प्रमुख पद पर रहते हुए चुनाव सुधारों व सख्ती से लागू करने का अभियान शुरू किया।

सरकारी योजनाओं से

संगता
सामृद्धि

राजस्थान राजस्थान का अहासिक उदयपुर शहर झीलों की ओरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। जहां नौ भर देश और दुनिया के पर्यटकों जमावड़ा लगा रहता है। यहां सुंदरता की मिसाल इसी से आई जा सकती है कि दुनिया के बड़े उद्योगपति और फिल्मी नारे वेडिंग स्थल के रूप में इसी र का चुनाव करते हैं। इसलिए शहर की भव्यता और सुंदरता तो ही बनती है। लेकिन इसी र से मात्र चार किमी की दूरी पर आ है मनोहर पुरा गांव। अनुसूचित ते बहुल इस गांव की आबादी भग एक हजार है और साक्षरता दर करीब पचास प्रतिशत है। र से करीब होने के बावजूद इस की अधिकतर आबादी विभिन्न कारी योजनाओं से वंचित है। मान में राजस्थान सरकार द्वारा य को मॉडलस्टेट बनाने के प्रयास सरकार द्वारा कई जनकल्याणकारा योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं को भी धरातल पर शत प्रतिशत लागू करना है। इन सब का अंतिम लक्ष्य राजस्थान की जनता को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे में सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, लकड़ी और धुएं वाले चूल्हे से महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना तथा शिक्षा, कृषि और चिकित्सा जैसे सुरक्षा की कई योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। परंतु इसके बावजूद इनमें से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ मनोहर पुरा गांव की जनता को नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में गाँव की एक बुजुर्ग महिला नंदू बाई बताती है कि वह पिछले 40 वर्षों से इसी गाँव में रहती आई हैं। पिछले वर्ष

उनके पात का स्वगवास हा गया। वह एक वर्ष से विधवा पेंशन के लिए दौड़ धूप कर रही हैं। परंतु जागरूकता के अभाव में वह विभाग से अपनी पेंशन शुरू करवाने में असफल रही हैं। नंदू बाई बताती हैं कि इस सिलसिले में वह कई बार ई-मित्र से भी मिल चुकी हैं, लेकिन वह भी उनके आवेदन को गंभीरता से नहीं लेता है और उसे अप्लाई करने में रुचि नहीं दिखाता है। हालांकि नंदू बाई बताती हैं कि यह काम प्रशासन का है कि वह उन जैसे बुजुर्गों के पेंशन की व्यवस्था करे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, मनरेगा गारंटी योजना से भी ग्रामीण जागरूक नहीं हैं। कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके पास जॉब कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन आज तक उन्हें मनरेगा से कभी काम नहीं मिला है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसके तहत

गांधी भा ग्रामाण पचायत स फाम 6
रकर काम मांग सकता है. लेकिन
न ग्रामीणों को ऐसी किसी प्रकार
जी जानकारी तक नहीं है. इसका
बसे अधिक नुकसान महिलाओं को
रहा है. मनरेगा से काम नहीं
लेने के कारण पुरुष काम की
लाश में शहर या अन्य राज्यों की
रफ पलायन कर जाते हैं, लेकिन
हिलाओं को घर की देखभाल के
कारण गाँव में ही रुकना पड़ता है.
से में गाँव की अनेक महिलाएं घर
जी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने
लिए शहर के बड़े घरों में ज्ञान
छांचा लगाने का काम करने का
जबूर है. इस संबंध में गाँव की
क 32 वर्षीय महिला जानकी देवी
हठती हैं कि उनके पति और उन्होंने
ई वर्ष पहले मनरेगा के तहत जॉब
गार्ड बनवाया था, लेकिन आज तक
न्हें कोई काम नहीं मिला है. इस
संबंध में वह कई बार पंचायत
गार्यालय भी गई लेकिन सिवाय

जागरूक नहीं ग्रामीण

गई भा ग्रामाण पचायत स काम 6 रकर काम मांग सकता है. लेकिन न ग्रामीणों को ऐसी किसी प्रकार जी जानकारी तक नहीं है. इसका बसे अधिक नुकसान महिलाओं को रहा है. मनरेगा से काम नहीं लेने के कारण पुरुष काम की लाश में शहर या अन्य राज्यों की रफ पलायन कर जाते हैं, लेकिन महिलाओं को घर की देखभाल के गरण गाँव में ही रुकना पड़ता है. से में गाँव की अनेक महिलाएं घर जी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने लिए शहर के बड़े घरों में जाड़ छांचा लगाने का काम करने को जबूर हैं. इस संबंध में गाँव की क 32 वर्षीय महिला जानकी देवी रहती हैं कि उनके पति और उन्होंने ई वर्ष पहले मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाया था, लेकिन आज तक नहीं कोई काम नहीं मिला है. इस संबंध में वह कई बार पंचायत गर्यालय भी गई लेकिन सिवाय आश्वासन क कुछ भा नहीं मिला. वह कहती है कि गाँव में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है और वह स्वयं इसी जाति से हैं. इनकी जाति के कई लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल चुका है, लेकिन उन्हें या उनके पति को आज तक काम नहीं मिला. उन्हीं की जाति की एक अन्य महिला शांति बाई नाराजगी के साथ कहती हैं कि मनोहर पुरा गाँव में कई बुनियादी आवश्यकताओं की कमी है. सबसे अधिक लोगों को रोजगार की जरूरत है. इसके लिए पुरुष और युवा गांव से पलायन कर रहे हैं. चुनाव के समय सभी दलों के नेता आकर सब कमी को दूर करने का आश्वासन देते हैं. लेकिन चुनाव के बाद कोई नेता पलट कर इस गाँव में नहीं आता है. शांति बाई कहती हैं कि जिन लोगों की पहुँच राजनीतिक दलों या विभाग से हाती है वह सभी योजनाओं का लाभ उठा लत ह, लाकन हमार ज लोग नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां और कैसे आवेदन करनी है? कोई हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार नहीं होता है. क ऐसे लोग हैं जिनके पास आज त उनका आधार कार्ड नहीं बना जिसके कारण वह किसी प्रकार व योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले हैं. उन्होंने बताया कि गाँव एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्यादेवी अकेले रहती हैं. इस बुढ़ापे उनका कोई नहीं है. वह कहीं करने में भी अक्षम हैं. ऐसे में उन लिए वृद्धा पेंशन कारगर सिद्ध सकता है. लेकिन आधार कार्ड न बने होने के कारण वह इसका ल उठाने से आज तक वंचित है. सि मनोहर पुरा गाँव के स्थाई निवासी ही नहीं बल्कि काम की तलाश 10 वर्ष पूर्व बिहार से आकर य बसा कई परिवार ऐसा है।

लोकतंत्र के शुभ को आहत करने

हकीकत ऐसे ही अवसरों पर सामने आती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के दुबारा आदेश के बावजूद संदेशखाली मामले के आरोपी को सीधीआइ के सुपुर्द करने में देरी होना न केवल समझ से परे है बल्कि यह लोकतंत्र एवं न्याय व्यवस्था की अवमानना है। इस पूरे प्रकरण से राजनीति समझ में आती है जो एक आरोपी को लेकर हो रही है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस शेख के मामले को एक राजनैतिक मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। आज भारत की आजादी का अमृत महोत्सव की परिसम्पन्नता पर एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्त्वों के राजनीति में खड़ी कर दी है कि शेख पर गंभीर आरोपों के बावजूद ममता सरकार उसे बचाने में लगी रही। शेख अपने इलाके संदेशखाली में महिलाओं का उत्पीड़न करता था और देह व्यापार के धंधे में भी संलग्न था। ये आरोप गंभीर हैं जिनकी गहनता से जांच होनी चाहिए। मगर हो यह रहा है कि राज्य सरकार शेख की रक्षा में नजर आ रही है और भाजपा लगातार आक्रमण कर रही है। विडम्बना यह है कि शाहजहां शेख कोई समाजसेवी न होकर वर्तमान दौर का मुनाफेबाज नेता, व्यभिचारी, हिंसा एवं अराजकता फैलाने का आरोपी है। वैसे तो ममता दीदी की सरकार में कई घोटाले हुए हैं मगर स्कूल घोटाले में शाहजहां शेख का नाम आने पर प्रवर्तन निदेशालय ने उसके खिलाफ जब जांच शुरू की तो हंगामा बरपा हो गया। इसकी वजह से जांच नहीं हो सकी।

विगत जनवरी माह के पहले सप्ताह में जब शाहजहां शेख के यहां संदेशखाली पुंछी तो स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उस टीम पर हमला बोल दिया। इनमें अधिसंख्य शेख के समर्थक ही थे। तृणमूल कांग्रेस एवं उनके नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों के बाद एक बार फिर इस सवाल ने जोर पकड़ा है कि जो लोग राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त बनाने की बात करते हैं, वे हर बार मौका मिलने पर अपने संकल्प एवं बेदाग राजनीति के दावों से किसी भी बात की जाते हैं? तृणमूल कांग्रेस में शेख जैसे नेताओं की कमी नहीं है। संदेशखाली से महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीनों के कब्जे को लेकर आ रही खबरें डराने वाली हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला कितनी तीव्री से किया जाएगा?

। चरित्र एक साधना है, तपस्या
। जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा
तोता है, उसे रोज कुछ न कुछ
गाहिए। उसी प्रकार राजनीतिक
चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और
ह सब दृढ़ मनोबल, साफ छवि,
मानदारी एवं अपराध-मुक्ति से ही
गप्त किया जा सकता है। लेकिन
ड़ा सवाल है कि कब मुक्ति मिलेगी
ख जैसे अपराधी तत्वों से राष्ट्र
गो? राजनीति में चरित्र-नैतिकता
गम्पन्न नेता ही रेस्पेक्टेबल
(सम्माननीय) हो और वही एक्सेटेबल
(वीकार्य) हो। राजनीतिक दलों के
बीच टकराव समझ में आता है,
लेकिन सरकार में बैठे लोगों से उम्मीद
की जाती है कि वे कार्यकर्ताओं और
अपराधियों के बीच के फासले को
उम्मीदें। चंद बोटों की खातिर देश
अलग-अलग हिस्सों में अपराधि
यों द्वारा भेजे जाएं गए अपराधियों

के दावों एवं लम्बे संघर्षों की कविश्वसनीयता धूमिल नहीं हो जायेगी। केवल सत्तारूढ़ तृप्तमूल कांग्रेस (टीएमसी) शेख को छह साल लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिशा कर अपनी पार्टी की अपराध-छोड़ को ढक नहीं सकती। आज जित तरह से हमारा राष्ट्रीय जीवन अंत सोच विकृत हुए हैं, हमारी राजनीति स्वार्थी एवं सकारी बनी है, हमारा व्यवहार झूठा हुआ है, चेहरों से ज्यानकाबैं ओढ़ रखी हैं, उसने हम सभी मूल्यों को धराशायी कर दिया राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापै में हैं। वक्त आ गया है जब देश व संस्कृति, गौरवशाली विरासत व सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखाएँ के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास कर होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग

